during 1996-97 to the Government of Himachal Pradesh for setting up of a 4 ETTCs. The name of the districts and the blocks wherein 4 ETTCs have been sanctioned are as under:

S. No.	Name of District	Name of Block
1.	Chamba	(i) Bhattiyal (ii) Tissa (iii) Salaoni
2.	Hamirpur	(iv) Bijhari

व्यवसायिक परियोजनाओं में प्रशिक्षण का उन्नयन

707. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यवसायिक परियोजना में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निर्धारित वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस तरीके से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1989 में 28 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना आरंभ की गई। परियोजना के मुख्य संघटक दिसम्बर 1997 में सम्पन्न हो गए। विश्व बैंक निधिकरण के साथ शेष चुनिंदा संघटक 31.12.1998 को सम्पन्न हो गए हैं।

परियोजना के सम्पूर्ण कार्यान्वयन स्तर से पता चलता है अधिकतर राज्यों ने वस्तुपरक लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं जबकि कुछ केन्द्रीय संघटक निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं। विभिन्न संघटकों के योजनावार निर्धारित लक्ष्य और अब तक की उपलब्धियां विवरण में दर्शायी गई हैं।

विवरण

व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना

15 फरवरी, 1999 के अनुसार योजनावार उपलब्धियां

क्रमांक	योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं		
1.	वर्तमान औ०प्र०सं० में उपकरणों का आधुनिकीकरण	378 औ०प्र०सं०	378 औ०प्र०सं०
2.	उपकरण अनुरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना	I. राज्य स्तरीय कार्यशालायें-19 II. औ०प्र०सं० में अनुरक्षण प्रकोष्ठ-100	स्थापित-19 स्थापित-93
3.	औ०प्र०सं० में श्रव्य-दृश्य सहायकों का प्रावधान	शामिल औ०प्र०सं०-387	शामिल औ०प्र०सं०-387
4.	औ०प्र०सं० में नये व्यवसाय	पाठ्यक्रमों की संख्या-376	आरम्भ पाठ्यक्रम —368

1	2	3	4
5.	स्व-रोजगार पाठ्यक्रम	41 औ०प्र०सं०	36 औ०प्र०सं०
6.	बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	18	18
7.	संबद्ध अनुदेश केन्द्र की स्थापना	38	38
8.	उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का विस्तार	33	30
9.	नए महिला औ०प्र०सं०/ विंगों की स्थापना	100 औ०प्र०सं०	96 औ०प्र०सं०
10.	महिला औ०प्र०सं०/ विंगों में गये व्यवसाय	64 औ०प्र०सं०	64 औ०प्र०सं०
11.	कर्मचारी प्रशिक्षण	3499	3652
12.	श्रव्य-दृश्य सहायकों पर कर्मचारी प्रशिक्षण	6007	6157
13.	कर्मचारी पद	4246	3712
14.	सिविल कार्य	438	430 (संपूर्णता के निकट शेष कार्य)

15 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार योजनावार उपलब्धियां

क्रमांक	योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
केन्द्र प्रवर्तित योजनायें			
1.	महिलाओं हेतु नये क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना	4 क्षे०व्या०प्र०सं०	अस्थायी स्थलों पर 4 नये क्षे०व्या०प्र०सं० कार्य कर रहे हैं।

1	2	3	4
2.	उपकरण अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना	6 उच्च प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरण अनुरक्षण केन्द्र	6 कार्यशालायें स्थापित
3.	क्षे०व्या०प्र०सं०/ रा०व्या०प्र०सं० का सुदृढ़ीकरण	वर्तमान क्षे०व्या०प्र०सं०/ रा०व्या०प्र०सं० का सुदृढ़ीकरण	वर्तमान क्षे०व्या० प्र०सं०/रा०व्या० प्र०सं० सुदृढ़ किए गए।
4.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में महिला प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण	महिला प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के महिला प्रकोष्ठ को सुदृढ़ किया गया।
5.	व्यवसाय परीक्षण व प्रमाणीकरण का सुदृढ़ीकरण	टी०टी० सैल का सुदृढ़ीकरण	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के टी०टी० सैल को सुदृढ़ किया गया।
6.	बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	कानपुर में बी०टी०सी० की स्थापना	स्थापित
7.	संबंद्ध अनुदेश केन्द्र की स्थापना	6 क्षे०शि०प्र०नि०	स्थापित
8.	उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना का विस्तार	6 उ०प्र०सं०	विस्तारित प्रशिक्षण सुविधाएं
9.	हाईटेक प्रशिक्षण	10 औ०प्र०सं० और 9 उ०प्र०सं० में हाईटेक प्रशिक्षण तथा एपैक्स हाईटेक की स्थापना	10 औ०प्र०सं० और 9 उ०प्र०सं० में स्थापित शीर्षस्थ हाईटेक संस्थान अस्थाई उपलब्ध स्थान में आरम्भ
10.	मीडिया संसाधन केन्द्रों (एम०आर०सी०) की स्थापना	10 एम०आर०सी०	10 एम०आर०सी० स्थापित
11.	सी-स्टारी कलकत्ता का सुदृढ़ीकरण	सी-स्टारी कलकत्ता का सुदृढ़ीकरण	सुदृढ़ किया गया

1	2	3	4
12.	तकनीकी सहायता	अनुदेशकों का प्रशिक्षण	केन्द्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
13.	एम०आई०एस० की स्थापना	20 केन्द्रों पर एम०आई०एस० की स्थापना	एम०आई०एस० केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार

708. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 15 जनवरी, 1999 के "दैनिक जागरण" में "रोजगार कार्यालय है या भ्रष्टाचार का अड्डा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) "दैनिक जागरण" का प्रकाशन दिल्ली के साथ-साथ कई अन्य स्थानों व इसके सैटेलाइट प्रकाशन बड़ी संख्या में भारत के कई कस्बों व शहरों से प्रकाशित किए जा रहे हैं। उपर्युक्त पत्र के दिनांक 15.01.1999 के इस समाचार को दिल्ली के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण शहरों के संस्करणों में से ढूंढने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि पृथक रूप से ब्यौरे के साथ इस विशेष समाचार की प्रति भेजने का कष्ट करें ताकि संबंधित राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा सके।

Backlog of Dues in PSUs

709. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the amount of dues of Provident Fund, Gratuity and ESI in PSUs in the country; State-wise; and

(b) the steps taken by Government to clear the backlog of dues?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) A statement indicating details of EPF and ESI dues in respect of PSUs is annexed. (*see below*) Necessary legal and penal action is already being taken to recover the dues from the defaulting PSUs. The concerned administrative Ministries/State Governments are also approached from time to time so as to ensure early liquidation of PF/ESI dues. As regards gratuity the liability for its payment under the payment of Gratuity Act, 1972 vests in the concerned employer. As such, the requisite information about gratuity is not centrally maintained.

Statement

(Rupees in Crores)

Name of the State	E.P.F. Dues	E.S.I. Dues
1. Andhra Pradesh	5.87	14.17
2. North-East	1.37	1.55
3. Bihar	8.46	2.83
4. Delhi	0.33	0.81
5. Gujarat	10.62	7.08
6. Haryana	9.68	0.29
7. Karnatka	0.19	6.30
8. Kerala	1.61	1.73